बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 94 ● नई दिल्ली ● बुधवार 21 जनवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली मंडल में टिकट चेकिंग अभियान से 31.88 करोड़ का राजस्व, पिछले साल से 17.74 फीसदी अधिक

नई दिल्ली । उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा और बिना टिकट प्रवेश करने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इससे रेलवे को मौजूदा वित्त वर्ष 31.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उत्तर रेलवे के अनुसार, अभियान का उद्देश्य यात्रियों को वैध टिकट के साथ यात्रा के लिए प्रेरित करना और रेलवे नियमों के उल्लंघन को रोकना है। वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल से दिसंबर 2025) के दौरान कुल 4.35 लाख मामले सामने आए। इनसे जुर्माने के तौर पर 31.88 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि के 3.66 लाख मामलों और 27.08 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 17.74 प्रतिशत अधिक है।

अनुछेद 15(5) पूरी तरह लागू हो, क्रियान्वयन की निगरानी का जिम्मा किसी नियामक को मिले - कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने संसद की एक समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान वाले अनुछेद 15(5) के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व किसी नियामक को दिया जाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस अनुछेद को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। अनुछेद 15 (5) के तहत निजी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के तहत देश में उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और अगले ही दिन इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। उन्होंने कहा, ऐसे किसी नियामक को संविधान के अनुछेद 15(5) के क्रियान्वयन की निगरानी का दायित्व दिया जाना चाहिए, जो आज से ठीक बीस वर्ष पहले अस्तित्व में आया हो। अनुछेद 15(5) को डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एनआईटी सहित

केंद्र द्वारा वित्त-पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी। उनका कहना है कि तब से अब तक ओबीसी समुदाय के लाखों छात्रों ने इस आरक्षण का लाभ उठाया है, जिससे करोड़ों लोगों को आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता मिली है। रमेश ने कहा, अनुछेद 15(5) सरकार को यह भी अनुमति देता है कि वह निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के छात्रों के लिए आरक्षण अनिवार्य कर सके। हालांकि, इसे बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा, छह मई 2014 को, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अनुछेद 15(5) की वैधता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा और यह साफ किया कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण की अनुमति है। हालांकि, वर्तमान में संसद द्वारा ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जो अनुछेद 15(5) को लागू कराए। उन्होंने उल्लेख किया, अगस्त 2025 में, शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें संसद से निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने वाला कानून पारित करने का आग्रह किया गया था। समिति ने पाया कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व अत्यंत और अस्वीकार्य रूप से कम है। रमेश ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर, कांग्रेस पार्टी अनुछेद 15(5) में निहित सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और मोदी सरकार से इसे पूर्ण रूप से लागू करने की मांग करती है।

दिल्ली-एनसीआर में और कंपाएगी ठंड : 21 से 23 जनवरी के बीच तेज बारिश और आंधी का अलर्ट

नई दिल्ली । भारी ठंड के बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 22 से 25 जनवरी के बीच तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब और उसके आस-पास के इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में एक और पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके कारण 23 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दिन तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में आज यानी 20 जनवरी को सुबह का तापमान 8 डिग्री तक रहेगा, वहीं, दोपहर में अच्छी धूप देखने को मिलेगी। लेकिन शुक्रवार 23 जनवरी से राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आने वाले 3-4 दिन सुबह के समय घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 22 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान जताया है। दिन में दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाने का भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। दिल्ली में 22 जनवरी को दोपहर के समय हवा की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, 21 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से 23 जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में बादल छाएंगे। सुबह के समय हल्का कोहरा भी देखा जाएगा। साथ ही, दिन में दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखी जा सकती है।

इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सर्द हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग की ओर से 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोनों ही दिन दिल्ली में आंशिक रूप से बादल नजर आने और सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है।

करप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, अब Central Govt अफसरों की जांच करेगी State ACB

नई दिल्ली ।

भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य पुलिस प्राधिकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों के आरोपी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास ऐसे मामलों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र है, और यह स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (एसीबी) जैसी राय स्तरीय एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए सीबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें राय की एसीबी द्वारा केंद्र सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि एक केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते, उसे केवल दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (सीबीआई) की निगरानी में होना चाहिए और उसके आचरण की राय द्वारा की गई कोई भी जांच कानूनी रूप से अमान्य है। इस तर्क को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएसपीई अधिनियम नियमित राय पुलिस को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर किए गए संज्ञेय अपराधों की जांच करने की अंतर्निहित शक्ति से वंचित नहीं करता है, चाहे आरोपी का नियोक्ता कोई भी हो।

फैसले का एक अहम पहलू सामान्य सहमति और पूर्व स्वीकृति संबंधी ढाँचों से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत भले ही आधिकारिक फैसलों की जाँच से पहले उचित सरकार- से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जाँच किसी विशिष्ट संघीय एजेंसी तक ही सीमित होनी चाहिए। जब तक कथित भ्रष्टाचार राय की सीमाओं के भीतर होता है, राय की जाँच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अधिकार है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को स्थानीय भ्रष्टाचार-विरोधी जाँच से बचने के लिए अपने संघीय दर्जे का इस्तेमाल करने से प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आपराधिक न्याय व्यवस्था में -सहकारी संघवाद- मॉडल को सुदृढ़ करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भ्रष्टाचार प्रशासनिक खामियों के कारण छिप न सके। राय एसीबी और सीबीआई के समवर्ती क्षेत्राधिकार की पुष्टि करके, सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधिक प्रभावी प्रवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों? मेनका गांधी की बात पर कहा- बिना सोचे बयान देना अवमानना के दायरे में

नई दिल्ली । आवारा कुत्तों के मुद्दे पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बिना सोचे-समझे दिए गए बयान न्यायपालिका के प्रति अवमानना के दायरे में आ सकते हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि संस्थागत परिसरों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी और नगर निगम अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे पहलुओं पर गंभीरता से विचार जरूरी है। सुनवाई के दौरान वकीलों ने बताया कि नगर निगमों की विफलता के कारण कचरा नहीं उठता, जिससे कुत्ते इकट्ठा होते हैं। शहरीकरण के साथ कचरा बढ़ा है, लेकिन उसके प्रबंधन में कमी है। अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या केवल भावनात्मक बहस नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी का भी सवाल है। नसबंदी और कचरा प्रबंधन जैसी मूल जिम्मेदारियां अधिकारियों की हैं। मेनका गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन से न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने तीखे सवाल किए। अदालत ने पूछा कि मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता रहने के दौरान बजटीय आवंटन और ठोस पहल का जिक्र आवेदन में क्यों नहीं है। पीठ ने यह भी जानना चाहा कि सार्वजनिक मंचों पर की गई टिप्पणियों के प्रभाव का आकलन क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने किन बातों पर कड़ी टिप्पणी की?

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आलोचना करने वाली टिप्पणियां अवमानना की श्रेणी में आ सकती हैं।

अदालत ने पूछा कि क्या वकील ने अपने मुवक्किल के बयान, पॉडकास्ट और सार्वजनिक भाषा पर ध्यान दिया।

न्यायमूर्ति ने कहा कि बिना सोचे-समझे सबके खिलाफ टिप्पणी करना स्वीकार्य नहीं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उदारता के चलते फिलहाल अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जा रही।

अजमल कसाब का जिक्र क्यों आया?

सुनवाई के दौरान बहस में अजमल कसाब का संदर्भ आया। इस पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने टिप्पणी की कि कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन यहां सार्वजनिक बयानों से ऐसा आभास बनता है। कोर्ट ने संकेत दिया कि जिम्मेदार पदों पर रहे लोगों से अधिक संयम की अपेक्षा होती है।

कुत्तों को खाना खिलाने पर क्या तर्क दिए गए?

एक वकील ने दलील दी कि कुत्तों को खाना खिलाने से वे भटकते नहीं, आपस में नहीं लड़ते और बीमारियां नहीं फैलतीं। प्रति कुत्ता सालाना खर्च का भी उल्लेख किया गया। तंजानिया का उदाहरण देते हुए कहा गया कि सहानुभूति को दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इन दलीलों को सुना, लेकिन प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर बनाए रखा।

प्रदूषण से मामूली राहत, दिल्ली-एनसीआर से हटा ग्रैप-4 का पहरा, मगर ये पाबंदियां अब भी लागू

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण के मोर्चे पर राहत की खबर है. दिल्ली की आबोहवा में आए सुधार और एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट के बाद पूरे इलाके में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को इसका ऐलान कर दिया. दिल्ली के एक्यूआई में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए 17 जनवरी को ग्रैप-4 लागू किया गया था. एक्यूआई 450 तक पहुंच गया था इसके तहत दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश और कई निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई थी. लेकिन अब आबोहवा में सुधार को देखते हुए सेहत पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया गया है. हालांकि स्टेज-1, 2 और 3 के प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेली बुलेटिन के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 378 दर्ज किया गया. यह प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट का संकेत है. इसी को देखते हुए सीएक्यूएम की उप कमिटी की बैठक हुई. इसमें दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में आए सुधार की समीक्षा की गई और ग्रैप-4 की बंदिशों को हटाने का फैसला लिया गया. सीएक्यूएम ने भले ही जीआरएपी-4 हटाने का ऐलान किया हो, लेकिन धूल नियंत्रण, कूड़ा जलाने पर रोक और अन्य पाबंदियां चरण-1, 2 और 3 के तहत सख्ती से लागू रहेंगी. इनमें गैरजरूरी निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण के अलावा स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक रहती है. पुराने डीजल वाहनों और अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाती है. स्कूलों में कक्षा 5 तक ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की सलाह दी जाती है. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर रोक लगाई जाती है.

बीजेपी में बिग बॉस का खेल चल रहा है - पवन खेड़ा

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि नितिन नबीन अब पार्टी मामलों में उनके बॉस हैं को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंज कसा है। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा और आरएसएस आपस में खेल खेलते रह सकते हैं। कभी (आरएसएस प्रमुख) मोहन भगवत किसी के बॉस बनते हैं, कभी मोदी किसी के बॉस बनते हैं। उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस का जिक्र करते हुए आगे कहा, क्या यहां बिग बॉस का खेल खेला जा रहा है? दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा से इस घटनाक्रम के बारे में पूछा गया, जहां उन्होंने कहा, चुनाव कहां है? इसे चुनाव क्यों कहते हैं? पहले राष्ट्रपति की घोषणा करते हैं, फिर कहते हैं कि चुनाव होगा, और फिर कोई चुनाव होता ही नहीं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं रही और चुनाव को ''प्रभावित करने का'' का मौका भी नहीं मिला। नितिन नवीन को मंगलवार को औपचारिक रूप से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। इस बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ''चुनाव कहां हुआ है, इसे चुनाव क्यों कहा जाए? आपने अध्यक्ष पहले घोषित कर दिया और फिर कहा कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। ज्ञानेश कुमार गुस्सा इसके विरोध में इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि उनकी कोई भूमिका नहीं है, वह कुछ प्रभावित नहीं कर सके, कुछ हेरफेर नहीं कर सके।'' उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री एवं भाजपा के लोग 'बिग बॉस' का गेम खेल रहे हैं। दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि पार्टी से संबंधित मामलों में यह युवा नेता उनका 'बॉस' होगा।

अर्थव्यवस्था को चोट

देश में जाली नोटों का कारोबार कई राज्यों में फैला हुआ है, इसमें से कुछ जाली करेंसी विदेशों से आई है तो कुछ भारत में ही तैयार की गई हैं। अभी तक पांच सौ, हजार और सौ-सौ के नकली नोट ही सिरदर्द बने थे परंतु अब पचास, बीस और दस रुपये के नकली नोटों का धड़ल्ले से चलन व्यवसायी, पुलिस और सौदागर छोटे-बड़े नकली नोटों की खपत ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में आसानी से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मीरापुर में बीती 18 जनवरी को थाना बिसवां पुलिस ने गुलजारशाह मेले से करीब एक लाख के नकली नोटों के साथ एक महिला सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीती 1 जनवरी को हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने नकली नोट बनाकर मार्केट में चलाने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया था। बीती 17 जनवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की पुसद पुलिस ने एक बड़े जाली नोट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। गत 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा तैयार कर उसे बाजार में खपाने वाले एक संगठित अन्तर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। बीती 13 जनवरी को गुजरात सूरत में नकली नोटों के रैकेट को लेकर पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में छोटे दुकानदारों को निशाना बनाकर नकली नोट चलाने वाला एक हीरा कारीगर को गिरफ्तार किया है। बीते साल नवम्बर में भोपाल पुलिस ने 21 साल के एक युवक को वीडियो देखकर अपने घर में नकली नोट बनाने के आरोप में पकड़ा था। आरोपी प्रिंटर, स्पेशल पेपर और प्रेस के अनुभव का इस्तेमाल कर असली जैसे 500-500 रुपए के नोट तैयार करता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश डिजिटल लेन-देन के मामले में अग्रणी बना हुआ है और यहां दुनियाभर में होने वाले लगभग आधे रियल टाइम लेन-देन डिजिटल भुगतान के जरिये ही होते हैं। हालांकि, नकदी रहित अर्थव्यवस्था का सरकारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के मार्ग में अभी तमाम बाधाएं विद्यमान हैं लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी की मौजूदगी बनी हुई है। देश में नकली नोटों का नेक्सस लगातार फैलता जा रहा है जो देश की बैंकिंग सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। नकली नोटों का यह नेटवर्क सीधे तौर पर भारत के बैंकों को निशाना बना रहा है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कई बैंकों की शिकायत पर एक केस दर्ज किया है जो काफी चौंकाने वाला है। इस मामले में 18 सरकारी और प्राइवेट बैंक शामिल हैं। बैंकों का कहना है कि उनके यहां करीब 11 हजार नकली करेंसी नोट जमा किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 34 लाख रुपये है। यह अपने आप में एक गंभीर और हैरान करने वाली बात है कि देश के बैंकों में इतने नकली नोट कैसे जमा हो पा रहे हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बीते सालों के दौरान नकली नोटों के पकड़े जाने के मामलों में तेजी आई है। इससे पता चलता है कि नकली नोटों का चलन तेज हुआ है। पिछले कुछ सालों में नकली नोटों की समस्या ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 500 रुपये के नकली नोटों में वित्त वर्ष 2019 से 2023 के बीच 317 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। जहां 2019 में यह संख्या 21,865 मिलियन पीस (एमपीसी) थी, वहीं 2023 में यह बढ़कर 91,110 एमपीसी तक पहुंच गई।हालांकि वित्त वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 85,711 एमपीसी पर आ गई। केंद्रीय बैंक आरबीआई के गवर्नर ने एक संसदीय समिति को जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल छह करोड़ से ज्यादा नोटों में से पांच सौ रुपये के 1.18 लाख नोट नकली पाए गए हैं। केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि इन नोटों की संख्या में एक साल में 37 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। जो यह दर्शाता है कि कालाबाजारी करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व देश में मुद्रा की मांग का गलत फायदा उठा रहे हैं। वर्ष 2016 में नोटबंदी के फैसले का उद्देश्य नकली नोटों और भ्रष्टाचार को रोकना था लेकिन मौजूदा आंकड़े इस कदम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। नकली नोटों का बढ़ता जाल संकेत देता है कि असामाजिक तत्व नए-नए तरीके अपनाकर इस चुनौती को और जटिल बना रहे हैं। विडंबना यह है कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा नोट में इस्तेमाल होने वाले आयातित कागज और नकली नोट छापने में शामिल ऑपरेटरों पर लगातार कार्रवाई के बावजूद यह गंभीर समस्या बनी हुई है। वास्तव में, हाल के वर्षों में भारत ने नकली नोटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने व कालेधन पर रोक के लिये डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी स्थिति खासी मजबूत की है। सरकार की सोच है कि कालेधन पर रोक लगाने के लिए नकद लेन-देन को हतोत्साहित किया जाए। नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था लेस कैश सोसाइटी की ओर अग्रसर है। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स 300 प्रतिशत तक बढ़े हैं। कैशलेस लेन-देन लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ-साथ हर लेन-देन से कालेधन को हटाते हुए क्लीन इकोनॉमी बनाने में भी मददगार साबित हुआ है। निस्संदेह, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत के आर्थिक लेन-देन तंत्र में क्रांति ला दी है। भुगतान के तमाम विकल्पों ने भारतीय नागरिकों के आर्थिक व्यवहार को बहुत आसान बना दिया है। हालांकि, अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो डिजिटल माध्यम से लेन-देन में परहेज करते हैं। असल में नकदी पर उनकी निर्भरता का मूल कारण डिजिटल शिक्षा का अभाव ही है। साथ ही इसके कारणों में भ्रष्टाचार और कर चोरी की नीयत भी शामिल है। ऐसे में सरकार को डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में रचनात्मक पहल करनी चाहिए। वहीं दूसरी आर्थिक अनियमितताएं करने वाले तत्वों से भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह भी चिंता की बात है कि नोटबंदी के नौ साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल बना हुआ है। बेशक, डिजिटल युग में भी 'नकदी ही राजा है' मानने वालों को रोकने के लिये जांच और कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। साथ ही इस दिशा में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश में लगी विदेशी ताकतों की नकली करेंसी के प्रसार में कितनी बड़ी भूमिका है। विगत में पाकिस्तान से हुए मनी व आतंकी संगठनों की मदद के लिये नकली करेंसी के उपयोग की खबरें सामने आती रही हैं। नकली नोटों के चलन को रोकने में सबसे बड़ी बाधा जागरूकता का अभाव है। शहरों में तो थोड़ी बहुत जागरूकता दिखती है, पर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के कम पढ़े-लिखे होने का फायदा उठाकर नकली नोटों के सौदागर अपना लक्ष्य आसानी से पूरा कर लेते हैं।

क्या रिश्तों में मिठास ला पाएंगे सर्जियो

दिल्ली दूर है? यह कहावत भारत में बहुत मशहूर है, मगर क्या अमेरिका के लिए भी दिल्ली दूर है? यह सवाल इसलिए, क्योंकि अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की घोषणा के बाद दिल्ली पहुंचने में सात महीने का वक्त लग गया, तो क्या अब ये कहावत चरितार्थ होने की उम्मीद की जानी चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। नए राजदूत सर्जियो गोर क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में मिठास वापस ला पाएंगे? इससे पहले भी कई बार भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति में विलंब के मौके आए हैं लेकिन अभी मसला ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रिश्तों में पहले की मिठास कड़वाहट में बदल चुकी है और अमेरिका भरोसे के संकट से जूझ रहा है। जनवरी 2021 में जब केनेथ जस्टर की राजदूत के पद से विदाई हुई थी तब से लेकर अप्रैल 2023 में एरिक गार्सेटी के आने तक यानी दो साल से ज्यादा वक्त तक भारत में अमेरिका का कोई भी राजदूत नहीं था, क्यों नहीं था, यह मसला जरा पेचीदा है, जो बाइडेन ने एरिक गार्सेटी का नाम तो फाइनल कर दिया लेकिन उन पर कई तरह के आरोप लग गए। आरोपों की जांच-पड़ताल में लंबा वक्त लगा, फिर गार्सेटी नई दिल्ली आए, लेकिन क्या इस बीच किसी और को राजदूत बनाकर दिल्ली नहीं भेजा जा सकता था? अमेरिकी सांसद मार्क वार्नर ने तब कहा था कि एक तरफ तो भारत से संबंधों को बेहतर बनाने की बात की जा रही है और दूसरी ओर एक राजदूत की नियुक्ति हम नहीं कर पा रहे हैं? उस वक्त यही माना जा रहा था कि बाइडेन भारत की हैसियत को कम मानने का संदेश देना चाहते थे, बहरहाल गार्सेटी भारत आए और मई 2025 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने भरोसे के व्यक्ति सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया, लेकिन उन्हें भी कार्यभार संभालने में करीब 7 महीने का वक्त लग गया, जबकि चीन समेत कई देशों में दिसम्बर, 2024 में ही राजदूत की नियुक्ति हो चुकी थी। सवाल फिर उसी विलंब का है। इसके साथ ही सर्जियो गोर को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, यानी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, मगर सवाल यही है कि इन जिम्मेदारियों के बीच वे भारत के साथ न्यायसंगत रिश्ते की कितनी वकालत कर पाएंगे? फिलहाल भारत में कार्यभार संभालते ही उन्होंने इस नजरिए का इजहार भी किया है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को बेहतर बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और मुझे इस बात की उम्मीद भी है क्योंकि वे ऐसी शख्सियत हैं जिनका सीधा संबंध डोनाल्ड ट्रम्प से है। उन्हें टीम ट्रम्प की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक माना जाता है।

> **जनवरी 2021 में जब केनेथ जस्टर की राजदूत के पद से विदाई हुई थी तब से लेकर अप्रैल 2023 में एरिक गार्सेटी के आने तक यानी दो साल से ज्यादा वक्त तक भारत में अमेरिका का कोई भी राजदूत नहीं था, क्यों नहीं था, यह मसला जरा पेचीदा है, जो बाइडेन ने एरिक गार्सेटी का नाम तो फाइनल कर दिया लेकिन उन पर कई तरह के आरोप लग गए। आरोपों की जांच-पड़ताल में लंबा वक्त लगा, फिर गार्सेटी नई दिल्ली आए, लेकिन क्या इस बीच किसी और को राजदूत बनाकर दिल्ली नहीं भेजा जा सकता था?**

खुद ट्रम्प ने भी सोशल मीडिया पर ट्रम्प परिवार से उनके रिश्तों का उल्लेख किया है और तारीफों के पुल भी बांधे हैं। ट्रम्प के बेटे जूनियर ट्रम्प से गोर की दोस्ती भी है, इसलिए यह भरोसा करने में कोई हर्ज नहीं है कि ट्रम्प को वे इस बात के लिए राजी करें कि इस इलाके में भारत के साथ रिश्तों की मिठास के बगैर चीन की नकेल कसना अमेरिका के लिए असंभव होगा। अन्य वैश्विक कारणों से भी अमेरिका के लिए भारत विश्वसनीय साझेदार हो सकता है, दरअसल पिछले करीब दस वर्षों में इसी सोच ने अमेरिका और भारत को एक पटरी पर लाने की कोशिश की थी लेकिन फिलहाल रिश्ते पटरी से उतरे हुए लग रहे हैं इसलिए काम जरा कठिन है। मगर मुझे विश्वास है कि वे कामयाब होंगे क्योंकि असंभव को संभव बनाने की कला उन्हें आती है। भारतीय संस्कृति को वे अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि भारत दोस्ती करने वाला देश है और ट्रम्प के चुनाव में किस तरह से भारत ने उनका साथ दिया था। नरम स्वभाव के सर्जियो गोर समझते हैं कि दो देशों के बीच व्यवहार और व्यापार को फलना-फूलना चाहिए। अवाम के बीच सद्भावना होनी चाहिए। एक बात तो तय है कि किसी भी देश के राजदूत का पहला दायित्व अपने देश के हितों को प्राथमिकता देना है। सर्जियो अमेरिका फर्स्ट नीति का मजबूर रूप से पालन करने वाले व्यक्ति हैं। ट्रम्प ने जब ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की थी और उसके ठीक बाद जूनियर ट्रम्प ने ग्रीनलैंड का दौरा किया था तो उनके साथ सर्जियो भी थे। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि नई दिल्ली में बैठकर भी सर्जियो का दिल अमेरिका के लिए ही धड़केगा और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर रिश्तों को बेहतर बनाने की जो जिम्मेदारी उनके पास है, उसमें यदि उन्हें सफलता हासिल करनी है तो उन्हें भारत की जरूरतों को भी समझना होगा। भारत में लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि जिस अमेरिका पर हमने भरोसा किया और रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की, क्या उसका बेहतर प्रतिसाद हमें मिला? अमेरिका आज भी पाकिस्तान की तरफदारी क्यों कर रहा है? रूस से चीन भी तेल खरीद रहा है, यूरोप गैस खरीद रहा है, खुद अमेरिका यूरेनियम पदार्थ खरीद रहा है, फिर केवल भारत पर ही टैरिफ का हमला क्यों? अब तो 500 प्रतिशत टैरिफ की धौंस दी जा रही है। क्या विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को धौंस से नियंत्रित करना चाहता है अमेरिका? सर्जियो गोर को इन सारे सवालों के जवाब तलाशने होंगे और भारत का पक्ष भी ट्रम्प के सामने रखना होगा, तभी रिश्तों में मिठास घोलने की कोशिश में वे कामयाब हो पाएंगे। भारत की शुभकामनाएं उनके साथ हैं।

सम्पादकीय...

प्रधानमंत्री मोदी का सच्चा दोस्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बेहद विरोधाभासी व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। आलोचक और विश्लेषक उन्हें गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अस्थिर व्यक्ति मानते हैं क्योंकि उनके बयान, नीतियां और कार्य समय के साथ या एक ही समय में एक-दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। भारत के संदर्भ में भी ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा दोस्त कहा तो कभी भारी-भरकम टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने नाटो, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, सीरिया के प्रति भी बार-बार रुख बदला है। ट्रंप खुद को आम जनता का प्रतिनिधि बताते हैं लेकिन उनकी नीतियां अक्सर अरबपतियों को फायदा पहुंचाने वाली होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अब एक नया पाखंड सामने आया है। अमेरिका ने भारत को 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने का न्योता दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर आमंत्रित किया है। गाजा पीस बोर्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद युद्ध के बाद गाजा में शासन और वहां हो रहे रिडेवलपमेंट की देखरेख करना है। गाजा के लिए ट्रंप ने 16 जनवरी को पीस ऑफ बोर्ड का ऐलान किया था। इसमें 20 बिंदुओं में शांति स्थापित करने का प्लान रखा है। इसे भविष्य में ग्लोबल झगड़ों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म के तौर पर देखा जा रहा है। यह न्योते 60 देशों को भेजे गए हैं। इसमें यूरोप के देश भी शामिल हैं। पहले गाजापट्टी में विध्वंस करने वाले इजराइल को खुली छूट देने और अब गाजा में शांति स्थापित करने की योजना बड़ी हास्यास्पद लगती है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ने गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी आमंत्रित किया है। अमेरिका के इस कदम से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान खुलेआम हमास का समर्थन करता है और शुरू से ही इजराइल का विरोध करता आया है। पाकिस्तान के अलावा ट्रंप ने तुर्की को भी आमंत्रित किया है जिससे इजराइल चिंतित हो उठा है। हमास ट्रंप के शांति योजना का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि यह योजना उसे पूरी तरह से निहत्था करने की साजिश है। ट्रंप की योजना के मुताबिक अगर कोई देश शांति बोर्ड का तीन साल से ज्यादा समय तक सदस्य बनना चाहता है तो उन्हें एक बिलियन डॉलर कैश देने होंगे। एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी तरफ डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को धमकियां किसी को रास नहीं आ रही। ट्रंप का टैरिफ कार्ड अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि यूरोप ने भी अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ट्रेड बाजूका को चलाने की तैयारी कर ली है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर एक फरवरी से 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप की इस जबरन वसूली की कूटनीति ने दशकों पुराने नाटो गठबंधन की नींव हिला दी है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील रोक दी है और ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए 93 अरब यूरो के जवाबी टैरिफ की योजना बनाई है। अगर यूरोपीय संघ के देश 93 अरब यूरो के जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो इससे अमेरिका हिल जाएगा। यह राशि इतनी विशाल है कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सैक्टर को हिलाकर रख सकती है।

सर्दियों में खो गई चेहरे की चमक? हरी सब्ज़ियों से पाएं स्किन पर निखार

आजकल तापमान में गिरावट के साथ ही हवा में ठंडक बढ़ रही है जिसकी वजह से त्वचा शुष्क, बेजान तथा निर्जीव सी दिखने लगती है। ठण्डक आपकी प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही आपकी त्वचा तथा बालों पर भी असर करती है। ऐसे में या तो आप लोशन क्रीम, मॉइस्चराइजर बार-बार लगाते रहें और या आप प्रकृतिक तरीकों से अपने शरीर की आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करें जिससे आप प्रकृतिक तौर पर सुन्दर दिखेंगी तथा मौसम का मिजाज आपकी त्वचा, बालों को प्रभावित नहीं कर सकेगा। सर्दियों के मौसम में प्रकृति हमें पालक, सरसों का साग, मेथी, बथूआ, हरे पत्तों का सलाद सहित ऐसी हरी पत्ते दार सब्जियां प्रदान करती है जिसके सेवन से हमारी त्वचा मौसम की मार को आसानी से झेल सकती है। इन हरी सब्जियों में एंटी आक्सीडेंट विटामिन, मिनरल तथा अन्य पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं जोकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ सुन्दरता को भी निखारते हैं। 1 ---गाजर- सर्दियों में बाजार में लाल रंग की गाजर सामान्यत: मार्केट में मिलती है जबकि बाकी सीजन में नारंगी रंग की गाजर देखने को मिलती है। गाजर विटामिन-सी से भरपूर होती है जिससे शरीर में कॉलाजन की उत्पत्ति होती है जो कि त्वचा को कोमल , मुलायम तथा लचीला बनाती है। गाजर में विद्यमान विटामिन ए से चेहरे पर झुर्रियां रोकने में मदद मिलती है। गाजर को फेस मास्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। गाजर को पानी में उबाल कर ठण्डा होने दें तथा ठण्डा होने पर इसे मसल कर बनी लुगदी को चेहरे पर लगाकर थोड़ी देर बाद चेहरे को साफ ताजे पानी से धो डालिए। इससे चेहरे की प्रकृतिक आभा में निखार आएगा। इसके नियमित प्रयोग से कील-मुहांसों तथा काले धब्बों से निजात मिलेगी।

2 --खीरा---- खीरे में सौंदर्य मिनरल ''सीलिका'' विद्यमान होता है जिसकी वजह से त्वचा की रंगत में निखार आता है तथा त्वचा कोमल व मुलायम हो जाती है। खीरा प्राकृतिक टोनर होता है। तैलीय त्वचा के लिए आप खीरे के रस को सीधे त्वचा पर लगाकर 15 मिनट बाद साफ पानी से धो डालें। खीरे के रस तथा गुलाब जल को मिलाकर बने मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद पानी से धो डाले। खीरे के गाढ़े गूदे में दो चम्मच गुलाब जल डालकर बलेंड कर लें तथा इस मिश्रण को चेहरे पर लगाकर 30 मिनट बाद ताजे साफ पानी से धो डालें। खीरा अस्ट्रिन्जन्ट होता है तथा टोनिंग और रिफ्रेशिंग के अलावा यह त्वचा के छिद्रों को बंद करता है तथा तैलीयपन को कम करता है खीरे को कद्दूकस करके या खीरे के रस को आंखों के इर्दगिर्द त्वचा पर लगाने से डार्क सर्कल कम होते हैं तथा त्वचा की रंगत में निखार आता है।

खीरा खाने से आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण त्वचा पर झुर्रियां और स्किन रेडनेस की समस्या से भी राहत मिल सकता है।

3 ----पालक--- पालक- सेहत का खजाना माना जाता है/ इसका जादुई असर खाने और लगाने दोनों से मिलता है/ पालक में फाइबर प्रोटीन विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन.के विद्यमान होता है और इसके अतिरिक्त इसमें आयरन फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है / पालक का फेस मास्क चेहरे की खूबसूरती निखारने में अहम भूमिका अदा करता है / दही और पालक का फेस पैक बनाने के लिए आप पांच पत्ते के हिसाब से तीन चम्मच दही ले सकते हैं।

इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर लें। पालक का पेस्ट बनाकर भी दही में मिक्स कर सकते हैं। इस पेस्ट को कम से कम 10 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखें।

चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं। इस पेस्ट से चेहरे का पिगमेंटेशन धीरे.धीरे कम होने लगेगा और आपकी त्वचा में ताजगी और रंगत में निखार आएगा / पालक का फेस मास्क बनाने के लिए पालक की 10--.15 पत्तियां, 1.2 बड़े चम्मच बेसन , 2.3 बड़े चम्मच दूध, 1 चम्मच शहद लें / पहले पालक की पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें ताकि मिट्टी ,गंदगी साफ हो सके / अब पालक की पत्तियों को मिक्सर में पीसकर फाइन पेस्ट तैयार कर लें। कांच के कटोरे में पालक का पेस्ट डालें और उसमें दूध, शहद और बेसन मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं और सूखने के बाद साफ ताजे पानी से धो लें इस पैक को हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत में निखार आएगा और त्वचा कोमल और मुलायम बनेगी / फेस मास्क के अलावा पालक का जूस भी सुंदरता निखारने में अहम भूमिका अदा करता है /पालक का जूस बनाने के लिए 2 कप पालक लें/ आपको इसके साथ एक सेब या फिर नाशपाती लेना है/ इसके अलावा नींबू का रस भी डाला जा सकता है/ तीन.चौथाई पानी डालकर इन सभी चीजों को ब्लेंडर में डालकर पीस लें और इसके जूस के सेवन से चेहरे पर झाइयां दूर होंगी और त्वचा में प्राकृतिक निखार आएगा /

4 ---पत्ता गोभी- सर्दियों में पायी जाने वाली सब्जियों में पत्ता गोभी में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। पत्ता गोभी में विद्यमान पौष्टिक तत्वों के सेवन से वजन कम करने तथा कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। जिससे आप जवाँ-जवाँ दिखेंगी। पत्ता गोभी में विद्यमान विटामिन त्वचा को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। पत्ता गोभी में विद्यमान मिनरल तथा सल्फर तत्वों की वजह से यह त्वचा को कोमल, लचीला तथा आकर्षक बनाती है। पत्ता गोभी को पानी में उबालकर पानी को ठंडा होने दें तथा इस पानी से त्वचा को साफ करें। पत्ता गोभी के जूस को पके केले की लुगदी तथा शहद में मिलाकर बने हेयर मास्क को बालों पर लगाकर 20 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो डालें। पालक- मूलत: फारस (ईरान) में पैदा हुए पालक को त्वचा के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। पालक विटामिन ए, सी, ई तथा के से भरपूर होता है जोकि त्वचा की सेहत तथा सौंदर्य के लिए उपयोगी माना जाता है। पालक के सेवन से त्वचा में निखार आता है तथा चेहरे पर काले धब्बे, कालिमा आदि से निजात मिलती है। पालक की ताजा पत्तियों को पानी से ब्लैंड करके इसे चेहरे पर 20 मिनट तक लगाकर चेहरे को ताजे साफ पानी से धो डालें।

5 ----सलाद- सर्दियों में सलाद आपको प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए।

सलाद में विद्यमान पोटेशियम तत्व आपकी त्वचा को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करते हैं जिससे रक्त संचार नियमित होता है और आप सुन्दर दिखने लगती है। सलाद में विटामिन ए,सी,के तथा जिंक की वजह से यह बालों की वृद्धि में सहायक होता है तथा बालों का असमय सफेद होने से रोकता है। सलाद को कच्चा खाना बेहतर होता है क्योंकि पकाने से इसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो सकते हैं। अगली बार जब भी आप बाजार जायें तो इन पौष्टिक सब्जियों की खरीदारी जरूर करें।

राष्ट्रव्यापी नुकसान की ममता बनर्जी सरकार को परवाह नहीं

पश्चिम बंगाल देश के लिए ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इससे होने वाले राष्ट्रव्यापी नुकसान की ममता बनर्जी सरकार को परवाह नहीं है। ममता बनर्जी का तौर-तरीका ऐसा बन चुका है मानो पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होकर एक स्वतंत्र देश हो। ममता किसी न किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से टकराती रही हैं। एक भी मौका केंद्र से टकराव का नहीं छोड़ती है और फिर खुद ही लोकतंत्र खतरे में है का नारा देकर सिर पर आसमान उठा लेती हैं। नया मामला प्रवर्तन निदेशालय के छापे की कार्रवाई का है। ईडी ने पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। सीएम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट पहुंच गईं। जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा- गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठवा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आई-पैक के कार्यालय और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के संबंध में संघीय एजेंसी के खिलाफ दो कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कराई। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी चुनाव से पहले उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के संवेदनशील दस्तावेज जब्त कर राजनीतिक प्रतिशोध कर रही है। पुलिस ने ममता बनर्जी की शिकायत पर ईडी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर औपचारिक जांच शुरू कर दी। यह मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट तक गया। कलकत्ता हाइकोर्ट ने रेड मामले में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी ईडी ने आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। एजेंसी का कहना था कि पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है, तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। याचिका को खारिज कर दी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर भारतीय न्याय संहिता के तहत 17 अपराधों की सीबीआई जांच की मांग की। याचिका में ईडी ने आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने ईडी की रेड में न सिर्फ बाधा डाली बल्कि अधिकारियों को डरा-धमकाकर सबूतों से छेड़छाड़ की। ममता सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि यह मामला चुनावों के बीच उठाया गया है और इससे राजनीतिक माहौल प्रभावित हो सकता है। ईडी चुनावी डेटा चुराने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सवाल किया, क्या लॉर्डशिप को लगता है कि हाईकोर्ट न्याय नहीं कर सकता? इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा, कृपया हमारे मुंह में शब्द न डालें। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले को गंभीर करार दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। हम इस पर परीक्षण करेंगे। अदालत ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया। ममता बनर्जी की केंद्र सरकार से टकराने की फेहरिस्त काफी लंबी है। इसका नमूना कोरोना महामारी में केंद्र के साथ टकराव, अम्फन तूफान को लेकर गृह मंत्री के साथ झगड़ा शामिल है। इस क्रम में बंगाली प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव को कौन भूल सकता है। बंगाल की सीमा पर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से आने वाले ट्रकों को लेकर भी केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव हुआ था। हुगली के तेलिनीपाड़ा में हुए दंगे को लेकर सोशल मीडिया में सवाल उठाने पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ हुई रिपोर्ट पर राज्य पुलिस ने सांसद अर्जुन सिंह और लॉकेट बनर्जी समेत कई नेताओं पर मामले दर्ज कर एक और टकराव को जन्म दिया था। टकराव की इस कड़ी में नया मामला पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति का है। राज्य के मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल इसी महीने 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। यूपीएससी ने ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट को वापस लौटा दिया। यूपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश को तकनीकी और कानूनी आधार पर रिजेक्ट कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम भेजे थे। लेकिन आयोग ने इस लिस्ट पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। यूपीएससी का कहना है कि पुरानी प्रक्रियाओं में कई खामियां छोड़ी गई थीं। इसके चलते वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को सही नहीं माना जा सकता है। नियमों के मुताबिक सरकार को एक तय समय सीमा के भीतर यह लिस्ट भेजनी चाहिए थी। यूपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। अब यह मामला कानूनी पेचीदगियों में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है।

सरकार के सामने अब कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आगवानी तक के लिए नहीं आई और ना ही बैठक में शामिल हुईं। पीएम का दौरा तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करना था। ओडिशा और बंगाल का दौरा तय हो जाने के बाद, दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ ही समय बताया गया था। लेकिन ओडिशा ने उस कार्यक्रम के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जबकि वो पीएम के बंगाल के दौरे से पहले था। ममता बनर्जी का आरोप था कि उन्हें पीएम मोदी का इंतजार करना पड़ा। जबकि पीएम को ही ममता का इंतजार करना पड़ा। पीएम के इंतजार करने की बात तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के ट्वीट से भी पुख्ता हुई थी। ममता बनर्जी अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर बैठक की जगह पहुंची जो कि हेलीपैड से सिर्फ 500 मीटर दूर था। पीएम से मिलकर वो 14.35 पर वापस भी चली गयीं। इसलिए वो सिर्फ 500 मीटर चलीं और 25 मिनट में वापस चली गईं। उनका पहले वापस जाना भी प्रोटोकॉल के खिलाफ था। इसलिए बंगाल सरकार का ये दावा गलत है कि ममता ने इंतजार किया बल्कि इसके उलट पीएम को ही इंतजार करना पड़ा था। केंद्र के साथ ममता के टकराव में बड़ा पेंच शारदा चिटफंड घोटाले ने भी बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही सीबीआई के अधिकारी तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल पहुंची थी और उसे राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले सीबीआई अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के घर घुसने नहीं दिया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद खुद सीएम ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। शारदा चिट फंड घोटाले की जांच का नेतृत्व कर रहे तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था और इसी मामले में पूछताछ करने सीबीआई वहां पहुंची थी। वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश का दौरा कर रहे थे कि अचानक उनके काफिले पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इस पर तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल की ममता सरकार को आड़े हाथ लिया था। दूसरे राज्यों में भी गैरभाजपा सरकारें हैं, किन्तु जिस तरह का विरोध ममता सरकार की तरफ से केंद्र का किया जाता रहा है, उससे साफ जाहिर है कि संविधान में मौजूद केंद्र के अधिकारों की उसे परवाह नहीं है। ममता का विरोध ज्यादातर मुद्दों पर कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा नजर आता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible] एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

टीएमयू में स्टुडेंट्स को दिए रोड सेफ्टी के टिप्स

मुरादाबाद।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-आरटीओ इंफोर्समेंट संदीप कुमार पंकज ने कहा, सीट बेल्ट का प्रयोग वाहन में सुरक्षा व्यवस्था- एयरबैग सिस्टम को प्रभावी बनाता है, जिससे गंभीर दुर्घटनाओं में जान बचाई जा सकती है। उन्होंने गोल्डन ऑवर-दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया, यदि कोई नागरिक घायल व्यक्ति की सहायता करता है, तो उसे गुड समैरिटन कानून के अंतर्गत पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की

सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में आरटीओ इंफोर्समेंट संदीप कुमार पंकज बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत

जान बचाने पर 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि और विशेष मामलों में 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार का प्रावधान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना, नशे में ड्राइविंग, स्टंट करना, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग कानूनन अपराध है। श्री संदीप तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी,

मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इससे पूर्व आरटीओ इंफोर्समेंट श्री संदीप कुमार पंकज, डीन स्टुडेंट्स वेलफेयर प्रो. एमपी सिंह, डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. प्रदीप तांगड़े, वाइस प्रिंसिपल डॉ. अंकिता जैन आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्र'जवलित करके वर्कशॉप का शुभारम्भ किया।

इस मौके पर सभी अतिथियों को पौधा भेंट करके स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आरटीओ इंफोर्समेंट श्री संदीप ने बताया, आरटीओ प्रशासन और आरटीओ प्रवर्तन के जरिए नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। चालान की स्थिति को ऑनलाइन भी जांचा जा सकता है। डीन स्टुडेंट्स वेलफेयर प्रो. एमपी सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने हाल ही में घटित कुछ दुर्घटनाओं का उदाहरण देते हुए छात्रों से जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। स्टुडेंट्स-दीया जैन एवम् शिवम सहरावत ने सड़क सुरक्षा विषय पर विचार रखते हुए सभी को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया। अंत में स्टुडेंट्स को यह संदेश दिया गया, सड़क पर जल्दबाज़ी नहीं, सुरक्षा ज़रूरी है। कार्यक्रम में डॉ. उपेंद्र मलिक, डॉ. हरितमा निगम, डॉ. रवेश जैन आदि के संग-संग डेंटल कॉलेज के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

वार्डन्स को सीपीआर का कराया अभ्यास

मुरादाबाद। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय नागरिक सुरक्षा उ0 प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार एमआईटी संस्थान में आयोजित वार्डन एवं स्वयंसेवक के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय सत्र के पंचम दिन प्रशिक्षण सत्र में सर्वप्रथम इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना की गई । प्रथम सेशन में आर के शर्मा, डिप्टी सीएमओ द्वारा बचाव के तरीके को समझाया गया और सीपीआर का अभ्यास कराया गया। दूसरे सेशन में डॉ अनुपमा मिश्रा द्वारा वार्डन की भूमिका पर चर्चा की गई । तत्पश्चात नीरज चक, उपनियंत्रक द्वारा अतिथि वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तीसरे सेशन में सतीश कुमार सहायक उपनियत्रक (व0वे0) द्वारा बचाव का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कार्यालय से चमन कुमार शर्मा, तुषार अग्रवाल मास्टर ट्रेनर अखिल अग्रवाल, विवेक कुमार यादव, डिविजन वार्डन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, मो खालिद, अशोक कुमार गुप्ता, शरीफ अहमद एड0, वसीम अंसारी, वसीम अख्तर, डॉ शफीक अहमद आदि ने उपस्थित रह कर सहयोग प्रदान किया।

नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद संभालने पर भाजपाईयों ने बांटी मिठाई

मुरादाबाद।

नितिन नबीन ने मंगलवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद जिला भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल ने पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई वितरण का आयोजन किया और कहा कि वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है।

पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि बिहार प्रदेश पांच बार के विधायक नितिन नवीन युवा नेता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी संगठन को मजबूती एवं पार्टी अनंत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कार्य करेंगे। नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पहले से और अधिक मजबूत होगी। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार प्रदेश में और वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में चौथी बार केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, भाजपा प्रांतीय परिषद सदस्य निमित जायसवाल,भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता,पूर्व महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर उपाध्यक्ष नवदीप टंडन, विशाल त्यागी, राहुल शर्मा,दिनेश सिसोदिया, शमी भटनागर,अश्विनी शर्मा, सुनीता शर्मा,शशी किरण,धर्मेश सैनी, अभिषेक चौबे,गुड्डू सैनी, अर्चित गुप्ता, अनूप महरोत्रा, विपिन प्रजापति, कपिल गुप्ता, योगेश गुप्ता,हेमा खत्री, रजनीकांत जाटव,सौरभ सक्सैना विशाल कुमार आदि शामिल रहे।

कामयाबी की इबारत लिखेगा 'उदीषा : चौपाला साहित्योत्सव-2026'

मुरादाबाद। मुरादाबाद मण्डल के इतिहास में पहली बार साहित्य, संस्कृति एवं बौद्धिक चेतना को समर्पित एक विराट आयोजन 'उदीषाः चौपाला साहित्योत्सव-2026' का आयोजन 22 से 26 जनवरी तक गांधी मैदान बुद्धिविहार मुरादाबाद में किया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि इस साहित्योत्सव का उद्देश्य जनसामान्य को विभिन्न भाषाओं के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य से परिचित कराना, उत्तर प्रदेश विशेषकर मुरादाबाद मण्डल की समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं लोक परंपराओं, खान-पान तथा बौद्धिक विरासत को व्यापक मंच प्रदान करना है। साथ ही यह आयोजन युवा पीढ़ी एवं विद्यार्थियों में साहित्य, संस्कृति एवं बौद्धिक मूल्यों के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में केवल एक उत्सव न होकर युवा चेतना को दिशा देने, सांस्कृतिक विरासत के सरक्षण तथा बौद्धिक परंपराओं के पुनर्स्थापना का एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें देश-प्रदेश के ख्यातिप्राप्त साहित्यकारों, प्रकाशकों एवं विचारकों की सहभागिता प्रस्तावित है। जिला प्रशासन के माध्यम से मुरादाबाद मण्डल के समस्त बुद्धिजीवियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि यदि उनके पास साहित्य, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान अथवा अन्य विषयों से संबंधित उपयोगी एवं बहुमूल्य पुस्तकें उपलब्ध हों, जिन्हें वे जनसामान्य के हित में प्रदान करना चाहते हों, तो वे पुस्तकों को उदीषाः चौपाला साहित्योत्सव-2026 के अवसर पर पुस्तक दान (ज्ञान-दान) के रुप में भेंट कर सकते हैं। दान स्वरुप प्राप्त पुस्तकों का उपयोग विद्यार्थियों, युवाओं एवं आम नागरिकों में ज्ञान के प्रसार, अध्ययन संस्कृति के विकास तथा बौद्धिक चेतना के संवर्धन हेतु किया जाएगा। यह पुस्तक दान समाज के लिए दीर्घकालिक बौद्धिक निवेश सिद्ध होगा। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से इस ऐतिहासिक साहित्यिक आयोजन में सहभागिता कर इसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा करता है।

उच्च शिक्षा अधिकारी ने परीक्षाओं का किया औचक निरीक्षण

मुरादाबाद।

मुरादाबाद-बरेली क्षेत्र के उ'च शिक्षा अधिकारी प्रो. सुधीर कुमार ने हिन्दू कालेज मुरादाबाद में चल रही परीक्षाओं का औचक निरीक्षण किया। जैसा कि विदित है वर्तमान में हिन्दू कालेज मुरादाबाद में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद तथा महात्मा 'योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की परीक्षाएं निर्धारित परीक्षा समय सारिणी के अनुरूप अलग-अलग पालियों में संचालित हो रही हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. सुधीर कुमार ने हिन्दू कालेज मुरादाबाद में संचालित हो रही परीक्षा के निरीक्षण हेतु शाम की पाली में कालेज परिसर पहुंचे। जहां पर उन्होंने प्रत्येक परीक्षा कक्ष में जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने नकल विहीन तथा शुचितापूर्ण परीक्षाओं के संचालन को लेकर शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। क्षेत्रीय उ'च शिक्षा अधिकारी ने इस दौरान कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए वरिष्ठ केंद्राध्यक्ष, सभी सहायक केंद्राध्यक्ष, आंतरिक उड़का दल तथा परीक्षा कार्य मे सहयोग कर रहे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से भी वार्ता कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने हिन्दू कालेज में चल रही परीक्षा की समस्त व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए नकल विहीन परीक्षा हेतु सभी शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और विद्यार्थियों का आह्वान किया कि सभी अपना-अपना दायित्व पूर्ण ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाएं। इस अवसर पर कालेज के प्राचार्य प्रो. सत्यव्रत सिंह रावत, शाम की पाली के केंद्राध्यक्ष प्रो. संजय शर्मा, प्रो. अनिल कुमार, प्रो. संजय रस्तोगी, प्रो. आनंद के. सिंह, प्रो. सत्येंद्र कुमार, प्रो. इला अग्रवाल, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. वीरेश कुमार, डॉ. एस. बी. यादव, डॉ. अकरम परवेज, डॉ. अनुपमा मिश्रा, के साथ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में आर. जे. यादव, जेड. ए. नकवी, संजय आर्य, अनुज यादव, रामेश्वर सिंह, विजेंद्र भार्गव, जयकिशोर आदि उपस्थित रहे।

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड ने सीधे किसान तक पहल के तहत किसान धन एनडीएससी पिपराइच, गोरखपुर का उद्घाटन किया

पिपराइच -गोरखपुर।

नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड ने अपनी किसान-केंद्रित पहल -किसान धन- सीधे किसान तक के अंतर्गत आज पिपराइच, गोरखपुर में ईश्वर वंदना के साथ हर्षोल्लास एवं गरिमामयी वातावरण में नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड डायरेक्ट सेल सेंटर (एनडीएससी) का शुभारंभ किया। इस भव्य उद्घाटन समारोह में श्री मुकेश मोहन मिश्रा (उप महाप्रबंधक), श्री राजेश द्विवेदी (प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय), किसान तथा कंपनी के प्रतिष्ठित थोक उर्वरक विक्रेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय किसान, उर्वरक विक्रेता एवं एन.एफ.एल. के अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया था तथा किसानों में विशेष उत्साह देखने को मिला। एनएफएल के इस डायरेक्ट सेल सेंटर के माध्यम से किसानों को कंपनी से सीधे उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक

उचित दरों पर उपलब्ध होंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, समय पर उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा कालाबाजारी एवं अनियमित भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा। यह व्यवस्था उर्वरक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ किसानों की लागत घटाने में भी सहायक सिद्ध होगी। एनएफएल अधिकारियों ने बताया कि 'किसान धन' पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को विश्वसनीय, पारदर्शी एवं सुलभ उर्वरक आपूर्ति उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों की आय सुदृढ़ बन सके। कुल मिलाकर, पिपराइच में 'किसान धन' डायरेक्ट सेल सेंटर का शुभारंभ क्षेत्र के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो किसान कल्याण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में देखा जा रहा है। अनेक कृषक बंधुओं द्वारा एन एफ एल के उच्च गुणवत्ता युक्त उर्वरक की खरीद भी बड़े उत्साह के साथ किया गया।

गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस पर 3000 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा, 22 और 25 जनवरी को दिल्ली नहीं जाएंगे भारी वाहन

गुरुग्राम। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए पिछले 20 दिनों से शहर में वेरिफिकेशन अभियान जारी है। माहौल को कोई भी अराजक तत्व बिगाड़ने न पाए, इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। तीन हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। रेलवे स्टेशन स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो व अन्य जगहों पर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं कई जगहों पर सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाले मुख्य समारोह और 23 जनवरी को होने वाली फाइनल रिहर्सल के लिए दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को एडवाइजरी जारी की है। इसके लिए 22 जनवरी गुरुवार शाम पांच बजे से शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के लिए भी भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। इसके तहत 25 जनवरी की शाम पांच बजे से 26 जनवरी की दोपहर डेढ़ बजे तक भारी वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी वाहनों को गुरुग्राम सीमा में ही रोक दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से शाम से ही बेरिकेडिंग की जाएगी। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारी वाहन ट्रक, हाइवा, डंपर, ट्राला व अन्य वाहन चलाने वाले इस एडवाइजरी के तहत ही अपने वाहन संचालित करें। गुरुग्राम और दिल्ली के बीच सिरहौल, कापसहेड़ा, आया नगर और इंद्राहेड़ा में बेरिकेडिंग की जाएगी। भारी वाहन हीरो होंडा चौक, शंकर चौक, महरौली बार्डर, सोहना, पटौदी, फरुखनगर, पचगांव केएमपी से डायवर्ट किए जा जाएंगे। जरूरी सेवाओं वाले वाहनों एंबुलेंस, मिल्क वैन, सब्जी की गाड़ियों, फायर ब्रिगेड और एयरपोर्ट जा रही गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा।

कब-कब रहेगी पाबंदी?

22 जनवरी को शाम पांच बजे से 23 जनवरी दोपहर डेढ़ बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए है दिल्ली बार्डर पर वाहन रोके जाएंगे। 25 जनवरी शाम पांच बजे से 26 जनवरी दोपहर डेढ़ बजे तक मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह के दिन गुरुग्राम सीमा पर वाहन रोके जाएंगे।

पचगांव से केएमपी डायवर्ट होंगे भारी वाहन

ट्रैफिक डीसीपी डॉ. राजेश मोहन ने बताया कि जयपुर साइड से हाईवे पर आने वाले भारी वाहनों को पचगांव चेक प्वाइंट पर रोका जाएगा और उन्हें केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इससे दिल्ली की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों पर भीड़ कम होगी। गुरुग्राम शहरी एरिया से निकलने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।

शहरी नक्सलवाद और घुसपैठियों पर मोदी का डबल अटैक, बोले- ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शहरी नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसने अंतरराष्ट्रीय आयाम हासिल कर लिए हैं और यह भारत के खिलाफ काम करना जारी रखे हुए है। राजधानी में भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, जहां नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, पीएम मोदी ने कहा कि एक और बड़ी चुनौती शहरी नक्सलवाद है।

शहरी नक्सलवाद का दायरा अंतरराष्ट्रीय होता जा रहा है। अगर वे साल में एक-दो बार भी मोदी के बारे में कुछ सकारात्मक ट्वीट करते हैं, या टीवी पर कुछ सकारात्मक कहते हैं, या अखबार में कुछ सकारात्मक लिखते हैं, तो कुछ पत्रकार उन्हें इतना अपमानित करते हैं कि उनका पीछा किया जाता है और उन्हें अछूत बना दिया जाता है। उन्हें इस तरह चुप करा दिया जाता है कि वे फिर कभी बोल न सकें। यही शहरी नक्सलवाद का तरीका है। मोदी ने आगे कहा कि वर्षों से ऐसे समूह भाजपा को अलग-थलग करते रहे हैं और देश भर में पार्टी सदस्यों को अछूतों की तरह मानते रहे हैं। अब देश इन शहरी नक्सलियों की हरकतों को समझ रहा है। शहरी नक्सली लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में घुसपैठियों के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि हमें हर चुनौती का पूरी ताकत से सामना करना होगा। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठियों की है। दुनिया में कोई भी देश अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता, और भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों और युवाओं के अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं दे सकता। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं; उनकी पहचान करना और उन्हें उनके देशों में वापस भेजना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, जो राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें पूरी ताकत से जनता के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। इसी बीच, नितिन नबीन ने आज सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई अन्य भाजपा नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ नितिन नबीन बिहार विधानसभा के पांच बार के सदस्य और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वे अपनी निरंतर संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाने जाते हैं। 36 में से 30 राज्य अध्यक्षों के निर्वाचित होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो आवश्यक 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर गई। चुनाव कार्यक्रम 16 जनवरी, 2026 को मतदाता सूची के साथ घोषित किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया कल, 19 जनवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच संपन्न हुई।

'राजनीति ऐशो-आराम नहीं, तपस्या है' अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बोले नितिन नबीन

नई दिल्ली। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में राजनीति की नई परिभाषा पेश की। कार्यकर्ताओं और युवाओं को संबोधित करते हुए नबीन ने स्पष्ट किया कि बीजेपी के लिए राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की एक साधना है। नितिन नबीन ने पार्टी की विचारधारा को रेखांकित करते हुए कहा, हम एक ऐसे दल के सिपाही हैं जहां राजनीति भोग-विलास या ऐशो-आराम के लिए नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या के लिए की जाती है। हमारे लिए कोई भी पद केवल एक अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी (उत्तरदायित्व) है।हर्ष के साथ उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने, सनातन परंपराओं और आस्था की रक्षा करने और देश को जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से बचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा,

15 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का आह्वान किया था। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति से दूर रहना समाधान नहीं, बल्कि सक्रिय योगदान देना ही समाधान है। नबीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए युवाओं को आगे आकर सकारात्मक राजनीति में भाग लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ''मैं युवाओं को यह भी बताना चाहूंगा कि राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं है। राजनीति सौ मीटर की दौड़ नहीं बल्कि मैराथन है, जहां गति नहीं बल्कि सहनशक्ति की परीक्षा होती है। आगे आइए और अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए इस राजनीतिक मैदान पर काम कीजिए। संगठन पर्व के समापन के बाद, जिसमें बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुए, मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में नबीन (45) को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वह बिहार से पांच बार विधायक रह चुके हैं और 14 दिसंबर को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले राय सरकार में कानून एवं न्याय, शहरी विकास और आवास मंत्री रह चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ और मंडल स्तर पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, भाजपा की निगरानी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह हर छोटी से छोटी बात पर नजर रख सकती है और एक दिन आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसके आप हकदार हैं। भाजपा के नए अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आगामी चुनावों से पहले राज्यों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण वहां चीजें किस प्रकार बदल गई हैं, जो हमारे सामने एक चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत और संकल्प तथा कड़ी मेहनत से इन पांच राज्यों में मजबूत नेतृत्व प्रदान करेंगे। नबीन ने हाल में तमिलनाडु में 'कार्तिगई दीपम विवाद का जिक्र करते हुए द्रमुक, कांग्रेस और 'इंडिया गठबंधन की अन्य विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा।

केंद्र का बड़ा कदम: यूटी उपराज्यपालों को मिले विशेष अधिकार, अब होगी सख्त कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर। केंद्र सरकार ने लोगों को गुमराह करने वाले झूठे और भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। खासकर कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले प्रचार पर अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में गृह मंत्रालय ने एक अहम अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत देश के 5 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब वे अधिकारी ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामलों में बिना देरी कार्रवाई कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत उपराज्यपाल और प्रशासक संदिग्ध संस्थानों की तलाशी ले सकेंगे, जरूरी दस्तावेज जब्त कर सकेंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर वे गजेटेड अधिकारियों को भी जांच और कार्रवाई के अधिकार सौंप सकेंगे।

नोएडा इंजीनियर मामला: एसआईटी जांच के बीच बिल्डर सीईओ अभय सिंह गिरफ्तार, प्रशासन पर उठे सवाल

नई दिल्ली। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को रियल एस्टेट फर्म एमजेह विलटाउन प्लानर्स के सीईओ अभय सिंह को 27 वर्षीय तकनीकी कर्मचारी युवराज मेहता की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया। युवराज मेहता की कार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में पानी से भरे नाले में गिर गई थी।

यह गिरफ्तारी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के बाद हुई है। एसआईटी प्रमुख भानु भास्कर, जो दल के साथ घटनास्थल पर गए, ने बताया कि वे पांच दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। भास्कर ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

हमने अधिकारियों और मृतक के परिवार के सदस्यों से बातचीत की है। जांच अभी शुरू हुई है। हम पांच दिनों की जांच के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। मेरठ जोन के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के नेतृत्व में गठित एसआईटी में मेरठ के संभागीय आयुक्त और पीडब्लू के मुख्य अभियंता शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, एसआईटी को पांच दिनों के भीतर मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपने का कार्य सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को लोकेश एम को नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) के प्रबंध निदेशक के पदों से हटा दिया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले डूबने के कारण दम घुटना और उसके बाद हृदय गति रुकना बताया गया है। इससे पहले, 16-17 जनवरी की रात को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेक्टर-150 चौराहे के पास एक नाले की सीमा तोड़कर पानी में गिरने से 27 वर्षीय युवराज मेहता की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद, पीड़ित के परिवार ने घोर प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि समय पर हस्तक्षेप से उनकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने दो घंटे तक संघर्ष किया था। एएनआई से बात करते हुए पीड़ित के पिता राजकुमार मेहता ने कहा, मेरा बेटा अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लोगों से गुहार लगा रहा था, लेकिन ज्यादातर लोग बस देखते रहे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। मेरे बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए दो घंटे तक संघर्ष किया। वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उसे बचा नहीं सके। उनके पास कोई गोताखोर नहीं था। इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की।

भाजपा राज में 'भ्रष्टाचार का ठोसीकरण अर्थव्यवस्था की नई अवधारणा - अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि सोने-चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि भ्रष्ट उपायों से अर्जित नकदी को बहुमूल्य धातुओं में बदलने की ''भ्रष्ट भाजपाई अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा राज में ''भ्रष्टाचार का ठोसीकरण अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा है, जिसमें मूल्य बढ़ने से, मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है।

भ्रष्ट-भाजपाई अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा

सपा प्रमुख ने कहा, ''भ्रष्ट-भाजपाई अर्थव्यवस्था की नयी अवधारणा। भ्रष्टाचार का ठोसीकरण, भ्रष्ट उपायों से कमाए गए, नकद धन को बहुमूल्य धातुओं में बदलना है। उन्होंने दावा किया कि बहुमूल्य धातुओं का मूल्य बढ़ने से घर-मोहल्ले, दुकान-बाजार में चोरी, सेंधमारी, लूटपाट, वाहनों, छिनैती की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जिसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की

आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा, ''इससे भाजपा राज में पहले से लचर पुलिस-व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है जिसके परिणामस्वरूप पुलिसिंग बेहद निष्क्रिय हो जाती है तथा अपराधी और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं।

सपा प्रमुख ने ये भी कहा...

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ''अगर विश्वास न हो तो एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की सहायता से इस मूल्य वृद्धि का विश्लेषण करा लिया जाए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी के वायदा भाव में 16,438 रुपये या लगभग 6 प्रतिशत की तेजी आई और यह 3,04,200 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमतों में भी मजबूती आई और यह नये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। फरवरी अनुबंध के लिए सोने का भाव 2,983 रुपये या 2.09 प्रतिशत चढ़कर 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले सप्ताह एमसीएक्स पर सोने के भाव में 3,698 रुपये या 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

एक ही परिवार के पांच लोगों की घर में मिली लाश, सभी के सिर पर लगी गोली

सहारनपुर। सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से मंगलवार की सुबह एक दंपति समेत परिवार के पांच शवों को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थाना सरसावा क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में एक मकान के एक कमरे में अमीन के पद पर कार्यरत अशोक राठी (40), उसकी पत्नी अनिता (37), मां विद्यावती (70), पुत्र कार्तिक (16) और देव (13) के शव बरामद हुए। अमीन के पास से तीन पिस्टल भी मिली हैं। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आशीष तिवारी ने बताया कि आज सुबह ही पुलिस को यह जानकारी मिली कि सरसावा की कौशिक विहार कॉलोनी में एक अमीन सहित उनके परिवारजनों के कुल पांच शव उन्हीं के मकान के एक कमरे में मिले हैं। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतकों के शव एक ही कमरे में पाये गये। उन्होंने बताया कि अशोक राठी के शव के बगल में तीन लोडेड पिस्टलें भी मिलीं। अमीन के पद पर कार्यरत रहे अशोक राठी सहित सभी के सिर पर गोली लगी है। तिवारी ने बताया कि गोली बहुत पास से मारी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा अशोक राठी सहित उनके पारिवारिक परिवेश की जानकारी ली जा रही है और पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौके से बरामद तीनों पिस्टल देशी हैं और वह लाइसेंसी हैं या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। एसएसपी ने अब तक की छानबीन के हवाले से बताया कि अशोक राठी को अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह मृतक आश्रित श्रेणी में अमीन की नौकरी मिली थी और वह नकुड़ तहसील में अमीन के पद पर कार्यरत था। उसके दोनों बेटे दसवीं और 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे।पुलिस ने अमीन अशोक राठी के घर को सील कर दिया है ताकि किसी भी स्तर पर जांच प्रभावित न हो पाये। एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव बरामद होने की सूचना मिलते ही सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी देहात सागर जैन सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा जा रहा है।

विधानमंडलों की जनता के प्रति सर्वोच्च जवाबदेही : विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण

चंडीगढ़।

86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मंगलवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने जनता के प्रति विधानमंडलों की जवाबदेही विषय पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि विधानमंडल जनता की भावनाओं, आशाओं और आकांक्षाओं को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से सदन में अभिव्यक्त करने वाली सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विधानमंडलों का मूल दायित्व जनता के हित में कार्य करना और उनके प्रति उत्तरदायी बने रहना है। कल्याण ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सत्ता का स्रोत जनता है और उसकी दिशा संविधान तय करता है।

भारत का संविधान न केवल शासन की व्यवस्था करता है, बल्कि विधानमंडलों को जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहने का स्पष्ट निर्देश भी देता है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों की भूमिका केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण, विवादों का समाधान, विकास की दिशा तय करना, सामाजिक सुधार और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जवाबदेही को केवल नियमों और प्रक्रियाओं तक सीमित कर देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक जवाबदेही विधानमंडल के चरित्र, कार्य-संस्कृति और संस्थागत क्षमता का संयुक्त प्रतिबिंब होती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, समितियां और वित्तीय नियंत्रण जैसे संसदीय उपकरण तभी प्रभावी होते हैं, जब उनके पीछे संवैधानिक दृष्टि, जनता के प्रति संवेदनशीलता और सशक्त संस्थागत ढांचा हो। हरियाणा विधानसभा द्वारा पिछले एक वर्ष में उठाए गए ठोस कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में विधानमंडल को अधिक जवाबदेह, सक्षम और सहभागी बनाने के लिए अनेक पहल की गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण योजना लागू की गई, लोकसभा के सहयोग से विधायी ड्राफ्टिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा विधायकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 में पटना में आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के प्रस्तावों को साकार करने के लिए भी कई पहल की गई। लोकसभा के सहयोग से हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकायों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देशभर के महापौरों और अध्यक्षों ने भाग लिया। हरियाणा विधान सभा में लेजिस्लेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का गठन किया गया। युवाओं को विधायी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए तीन युवा संसद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा विधान सभा की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त युवा मामलों और पर्यावरण से संबंधित दो नई समितियों का गठन किया गया। विज अध्यक्ष ने कहा कि इन सभी प्रयासों के माध्यम से हरियाणा विधानसभा एक गतिशील, एक विधायिका की भावना के अनुरूप पारदर्शी और सहभागी विधायी प्रणाली के निर्माण की दिशा में निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सशक्त विधायिका, जागरूक समाज और मजबूत संस्थागत क्षमता के बिना विकसित भारत-2047 का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शब्दों को उद्धृत करते हुए कहा कि सदन को नैतिक शक्ति और जनमत की स्वीकृति ही प्रशासन को शुचिता सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा आधार है।

'कल्याण ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सत्ता का स्रोत जनता है और उसकी दिशा संविधान तय करता है। भारत का संविधान न केवल शासन की व्यवस्था करता है, बल्कि विधानमंडलों को जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहने का स्पष्ट निर्देश भी देता है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों की भूमिका केवल कानून निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण, विवादों का समाधान, विकास की दिशा तय करना, सामाजिक सुधार और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उनके प्रमुख दायित्वों में शामिल है।

बीजेपी संग गठबंधन की अटकलों पर ओवैसी का इनकार , कहा- हमारा रास्ता बिल्कुल अलग

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि समुद्र के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते। एनआईए को दिए एक विशेष साक्षात्कार में ओवैसी ने अकोट में हुई हालिया घटना का जिक्र किया, जिसमें एआईएमआईएम पार्षदों ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि अकोट में एआईएमआईएम के पांच पार्षदों ने चुनाव जीता था और पार्टी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। ओवैसी ने कहा कि शुरुआत में पार्षदों ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस समूह में वे शामिल हुए हैं वह बीजेपी से जुड़ा हुआ है।

ओवैसी ने बताया कि इसके बाद पार्टी ने उन्हें तुरंत नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अपना समर्थन वापस लेने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि बाद में यह बात सामने आई कि भाजपा नेता के बेटे को सह-विकल्प के माध्यम से पार्टी में शामिल किया गया था, जिसके बाद इम्तियाज जलील ने पार्षदों को पार्टी से निलंबित कर दिया। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि एआईएमआईएम प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों से गठबंधन करने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि यह पता चला कि जब भाजपा नेता के बेटे को सह-विकल्प के माध्यम से पार्टी में शामिल किया गया, तो इम्तियाज जलील ने

उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। चाहे भाजपा हो, एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार, अगर वे उनके साथ जाते हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए, ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने हाल के चुनावों में 125 सीटें और लगभग एक महीने पहले हुए नगर निगम चुनावों में लगभग 85 सीटें जीती थीं। उन्होंने आगे कहा कि एआईएमआईएम के पास अब राज्य भर की नगर परिषदों और नगर निगमों में 200 से अधिक पार्षद हैं। ओवैसी ने कहा कि इस बार हमने 125 सीटें जीती हैं। लगभग एक महीने पहले हुए नगर निगम चुनावों में हमारे लगभग 85 उम्मीदवार विजयी हुए थे। नगर परिषदों और नगर निगमों को मिलाकर देखें तो अब तक हमारे 200 से अधिक पार्षद विजयी हो चुके हैं। अगर कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती है, तो स्पष्ट है कि उस पार्टी में कुछ कमियां हैं। हम वर्षों से जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में एआईएमआईएम ने महत्वपूर्ण बढ़त दर्ज की, पिछले चुनावों की तुलना में अधिक सीटें जीतीं और बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में आठ सीटें हासिल कीं।